फरीदाबाद

मजदूर समाचार

मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 96

जून 1996

19 जून को सुबह दस बजे, 20 को शाम 5 बजे और 21 जून को रात 8 बजे इस अखबार पर मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी में चर्चा होगी। हर कोई इसमें भाग ले सकता है।

एकता बनाम सामुहिकता

एकता और लीडर

जब कोई लीडर कहता है कि " एकता है" तो क्या उसका मतलब यह नहीं होता कि सब लोग उसके पीछे हैं?

" एकता है" दोहराने वाले मजदूरों को क्या इस बात की जानकारी होती है कि किस बात के लिये एकता है?

जिन मजदूरों में " एकता है" वाली बात होती है क्या वे एक-दूसरे से यह पूछते नहीं मिलते कि क्या बात है? क्या हो रहा है?

जिसे **एकता** कहा जाता है वह समूह का बल होता है
जिसे इस्तेमाल करने की स्थिति में लीडरशिपें होती हैं।

बिना जाने कि किसलिये जा रहे हैं चल देना,
बिना पता हुये कि किसलिये कदम उठा रहे हैं कदम उठा देना
एकता है।

कहने पर ही चलना, खड़े होना, बैठना, मुड़ना एकता का चरित्र है, सार है।

इसीलिए लीडरों का पूरा जोर एकता बनाये रखने पर होता है।

मजदूर कोई सवाल उठाते हैं तो एकता भंग होती है।

एकता के वास्ते **मजदूरों द्वारा अपने मुँह बन्द रखने जरूरी हैं।**

लीडर ही बोलेंगे — एकता की अनिवार्य आवश्यकता है।

मजदूरों के सोचने-समझने-बोलने-कुरेदने-आगेपीछे की बातें जोड़ने से एकता भंग होती है।

एकता को बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि अपने मन-मस्तिष्क में उठती शंकाओं - सवालों पर मजदूर खुसर-पुसर भी नहीं करें,

मीटिंग में एकत्र लोगों में तो हरगिज नहीं बोलें।

ध्यान रखें कि लीडर जब " किसी को कुछ कहना है तो बोले" कहते हैं तब उनका मतलब होता है कि समर्थन में कुछ कहना है तो बोलें।

छत्तीस भंगिमाओं, छत्तीस रूप-रंग, छत्तीस लटके-झटकों के जरिये लीडर लोग मैनेजमेन्टों की पालिसियाँ लागू करवाने के प्रयास करते हैं।

एकता के वास्ते लीडरों के लिए झूठ बोलना जरूरी होता है।

इसीलिए लीडर खुलेआम झूठ बोलते हैं।

मजदूरों की एकता मैनेजमेन्टों के बहुत काम की है।

एकता नेताओं की पवित्र गऊ है।
आओ इसका वध करें।

सामुहिकता और मजदूर

सवाल है, " हर कोई क्या कर सकता/सकती है?" प्रश्न जटिल है। इसे सरल करने, आसान करने के लिए मसले को फैक्ट्रियों के दायरे में देखते हैं।

सब जानते हैं कि प्रत्येक मजदूर को शिफ्ट, डिपार्टमेन्ट, फैक्ट्री स्तर की समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, डायरेक्ट जानकारी होती है। फैक्ट्री में रोज मिलना होता है। इसलिए हड़बड़ी में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी बात को उलट- पुलट कर कई बार उसका हिसाब लगा सकते हैं। मजबूरों के यह माफिक है। प्रत्येक मजदूर के यह माफिक है क्योंकि झिझक और डर मजदूरी-प्रथा में हर वरकर की नियति है।

कुछ भी करने से पहले और कुछ भी करने के दौरान भी मजदूर उसके बारे में विभिन्न पहलुओं से विचार कर सकते हैं तथा परिवर्तन कर सकते हैं। **कदम उठाने में ही नहीं बल्कि कदमों के बारे में विचार-विमर्श में भी प्रत्येक मजदूर आसानी से हिस्सा ले सकता/सकती है।**

मजदूरों के कदमों के डायरेक्टली खिलाफ हैं चार्जशीट, सस्पैन्ड और फुटकर व पुलिस-रूपी संगठित गुन्डे। कोई मजदूर आगे बढ कर बोलता/बोलती है तो मैनेजमेन्ट और लीडर उसे धार पर धर लेते हैं। इक्का-दुक्का मजदूर ही आगे बढ कर बोल सकता/सकती है, हर मजदूर यह नहीं कर सकता/ सकती।

कोई आगे बढ कर क्यों बोले?
इसकी जरूरत ही क्या है?

मजदूर जब मिलजुल कर कदम उठाते हैं और कोई आगे नहीं होता/होती तब
मैनेजमेन्ट चार्जशीट किसे दे?
सस्पैन्ड किसे करे?
गुन्डे और पुलिस किस पर हाथ डालें?
किसे चुपके से दो पैसे दे?

यह अनबुझ पहेलियाँ हैं क्योंकि इनके कोई उत्तर होते ही नहीं हैं। यह प्रश्न मैनेजमेन्टों को सिरदर्द कर देते हैं।

प्रत्येक मजदूर जो कर सकता/सकती है वह एक और खूबी लिये है। मजबूरियों में उन्नीस-इक्कीस के फर्क की वजह से कोई मजदूर डेढ फुट के कदम के लिये तैयार होता/होती है तो कोई छह इंच के कदम के लिये ही।

(बाकी पेज चार पर)

शेषन शेष

दिनांक 20.4.96 को भिवानी के निर्वाचन अधिकारी, उपायुक्त टी सी गुप्ता महोदय ने जब अपनी पाइलेट रिहर्सल को पीठासीन अधिकारियों के अपमान से आरम्भ किया तो क्रोधित तीसरे दर्जे के कर्मचारियों ने चुनाव ड्युटी का बहिष्कार करने की घोषणा कर डाली और शेम-शेम के नारे लगाये। वातावरण ठन्डा तभी हुआ जब श्रीमानजी ने जनसमूह से क्षमायाचना की।

इसके पश्चात भिवानी जिले के बाढड़ा- 63 की 177 चुनाव पार्टियों को जब 26.4.96 को चुनाव की सामग्री देने के पश्चात पैकेट डिनर दिया गया तो मालूम हुआ कि निर्वाचन आयोग की तरफ से उस भोजन का भत्ता प्रति व्यक्ति 50 रुपये मिला है जबकि भोजन मुश्किल से 5 रुपये का था और वह भी बिगड़ा हुआ बदबूदार। सभी कर्मचारियों ने अपने-अपने पैकेट बाढड़ा निर्वाचन इन्चार्ज, डी.आर.ओ. महोदय के सिर में दे मारे और गन्दा भोजन खा कर गन्दे पीपों (मतपेटियों) को उठा कर गन्दे ट्रकों में रखने से साफ इनकार कर दिया।

जब सभी प्रकार की याचना-प्रार्थना असफल हो गई और दो बजे तक एक भी कर्मचारी ट्रक में नहीं बैठा तो प्रत्येक पार्टी के पीठासन अधिकारी को प्रत्येक व्यक्ति की दर से सौ-सौ रुपये नकद बाँटे।

दो दिन के भूखे-प्यासे कर्मचारी जब भरी हुई मतपेटियों को जमा करवाने रात को देर से अपने केन्द्र पर पहुँचे तो 177 पार्टियों को एक ही खिड़की पर लम्बी लाइन में खड़ा कर दिया गया मानो वे भेड़-बकरियाँ हों। कर्मचारियों ने सामान जमा करवाने का बहिष्कार किया तब जा कर चार काउंटर बनाये गये। उसके पश्चात सामुहिक शक्ति के डर से कर्मचारियों के लिये रात को बसें चलाई गई।

3.5.96 — एक अध्यापक

किस्सा एक और परिवार का

आज एक परिवार की कहानी सुनाता हूँ। जब मैंने पहली बार उस परिवार में प्रवेश किया, यानि कम्पनी में नौकरी पर लगा तब मेरे होने वाले बॉस ने, जो उस समय सुपरवाइजर था, मुझे समझाया : " देखो, यह कम्पनी नहीं एक परिवार है। डायरेक्टर (जिसे वो मालिक कहते थे) और उनकी पत्नी हमारे माई-बाप हैं। हम सब उनके बच्चों के समान हैं। हम में से कोई बड़ा भाई है तो कोई छोटा भाई।"

सुपरवाइजर के इतना कहने पर मेरा मन भर आया था। दफ्तर की चारदिवारी के अन्दर मैं अपने माँ,बाप, भाई, बहन को देखने लगा। आपकी दुआ से मैं वैसे भी कुछ ज्यादा ही भावुक हूँ। मेरे बॉस , मेरे बड़े भाई के प्रोत्साहन से मैं जी-जान लगा कर रात-दिन काम करने लगा। मेरी पगार मात्र 2500-3000 रुपये थी मगर उसपे कौन ध्यान देता। मेरे ध्यान में परिवार की खुशहाली थी, पगार जैसी छोटी-मोटी चीज पे ध्यान देना शर्म की बात थी। वैसे भी हर छह महीने में पगार बढाने का वादा वो कर ही चुके थे। ऐसे में माँ-बाप के चेहरों पे मुस्कान लाना मेरा एकमात्र कर्तव्य था। मेरे उस समय तथाकथित शुभचिन्तक मुझे भड़काते थे यह कह कर कि मेरी पगार कम थी। मैं उन लोगों को जवाब देने को बिल्कुल तैयार होता था और मैं तुरन्त जवाब देता था, " प्यार से माँ-बाप जितना दें उसी में खुश रहना चाहिये। जो माँ-बाप की मजबूरियाँ न समझे वो सन्तान कैसी।"

मेरा जवाब सुनके वो हक्का-बक्का हो जाते थे और मैं नाइट ड्युटी करने के बाद फिर सुबह 10 बजे सीना तान के आफिस भागा करता था — बड़े भाई ने मीटिंग बुलाई है, पहुँचना जरूरी है।

ऐसे में एक बड़ा-सा प्रोजेक्ट आया। हम सबने जी-जान लगा दी — प्रोजेक्ट भलीभाँति पूरा कर दिया। प्रोजेक्ट खत्म होने पर बाबुजी ने जब हमें कुछ पैसे देने चाहे तो हमारा सबसे बड़ा भाई बहुत ही गुस्सा हो गया। उन्होंने अपने शब्दों में अभिमान व्यक्त करते हुये कहा, " बाबुजी क्या आप हमें पराये समझते हैं? आज तक हम अपने आप को परिवार के सदस्य समझते रहे हैं। हमें पैसे नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिये।"

बड़े भाई के भाषण से हमारी सबकी आँखें भर आई थी। हम सबने भी पैसों के बदले आशीर्वाद माँगा। बाबुजी प्रसन्न हो कर हम सबको एक दिन होटल में खिलाने ले गये। पिता के इस प्यार से हमारा जी भर-भर गया था। हम फिर से मन लगा के काम शुरु ही करने वाले थे तो सुनने में आया कि बड़े भाइयों में किसी-किसी की प्लेट के नीचे पैसे भी मिले थे।

सुनके मुझे बहुत दुख हुआ। हमने सोचा कि शायद वो भाई लोग भाड़े के होंगे। फिर मन मार कर काम करने लगा। इतने में मेरी पगार बढाने का समय निकल चुका था। पहली बार मेरी नजर पगार पर पड़ी पर फिर भी मैंने नजरअन्दाज कर दिया — अपनों से क्या माँगना, समझदार होंगे तो खुद दे देंगे। माँग के भिखमँगा बनना मेरे उसूल के खिलाफ था। समझने वाले अगले छह महीने निकल जाने पर भी नहीं समझे — शायद समझना उनके उसूल के खिलाफ था। आखिर में मैंने अपना दुख-दर्द ऊपर वाले भाई के सामने रखा तो उन्होंने परिवार की आर्थिक हालत का ब्यौरा दिया — उस समय आमदनी बहुत ही कम थी और मुश्किल से हमारी पगार दी जा पा रही थी। मगर उन्होंने कहा कि अवसर मिलने पर बाबुजी को जरूर बतायेंगे।

इस बीच काम बहुत बढ चुका था। थकावट मेरे चेहरे की साथी बन गई थी। साथ ही चलने लगे थे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट — परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिये ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी थे। एक दिन मैं लँच करने वहाँ रोटी शायद कुछ सूखी थी — रोटी के 32 टुकड़े चबाने के लिए 32 सैकेन्ड की बजाय शायद [illegible] लिये होंगे। इस देरी के कारण मुझे बड़े भाई से डाँट पड़ी। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने जवाब दिया, " वैसे ही मेरी पगार बढने का कोई नाम-निशान नहीं है और उसके ऊपर मुझे ये डाँट सुननी पड़ रही है।"

मेरे बोलने पर बड़ा भाई परिवार की खुशहाली के लिये बलिदान और निष्ठा की तोता कहानी सुनाने ही वाला था कि मुझे गुस्से में ही बारिश में धूप की तरह हँसी आ गई और मैंने कहा, " हमने कथा-कहानियों में माँ-बाप द्वारा अपना पेट काट कर बच्चों के पेट भरने के किस्से सुने थे मगर शायद दफ्तरी परिवार कुछ अनोखी चीज है — यहाँ बच्चों की जेब काट कर ही खुशहाली हासिल होती है।"■

— मृत्युंजय

डाल बिन उल्लू

12 घन्टे की नाइट ड्युटी कर के लौटे एक मजदूर ने कहा, " मुझे इस समय ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे जूतों से पीटा हो और मेरी रग-रग तोड़ दी हो। थका-टूटा तो हूँ ही, मैं बहुत अपमानित भी महसूस कर रहा हूँ।"

प्लाट 134, सैक्टर-25 स्थित **रबड़ टैक फैक्ट्री** में 45 मजदूर काम करते हैं और सब कैजुअल हैं। 12-12 घन्टे की दो शिफ्टें हैं और मैनेजमेन्ट की सख्त हिदायत है कि फैक्ट्री में कोई बैठेगा नहीं। दिन में तो वरकर किसी तरह गाड़ी खींच लेते हैं पर रात में बिना डाल के उल्लू की तरह 12 घन्टे खड़े-खड़े काम करते समय मजदूर नींद के झौंके में गिर जाते हैं। चोट बहुत लगती है।■

बाँटने वाले फ्री में यह अखबार बाँटते हैं। बाँटने में हिस्सा लेने के लिये यह जरुरी नहीं है कि आप सड़क पर खड़े हो कर बाँटें — आप मजदूर लाइब्रेरी से दस-बीस-पचास प्रतियाँ ले कर उन लोगों को पहुँचा सकते हैं जिन्हें अखबार देना आपको उपयोगी लगे।

आर्थिक सहयोग देने के इच्छुकों का जो यह प्रश्न होता है कि "पैसे किसे दें ? " उन्हें बता दें कि जिनसे आप अखबार लेते हैं उन्हें बेझिझक पैसे दे सकते हैं। मजदूर लाइब्रेरी आ कर भी आप पैसे दे सकते हैं।

इस अखबार में अपनी बात कहें। आपका नाम हम किसी को नहीं बतायेंगे। अपनी बात छपवाने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। कविता, कहानी, चुटकुलों, चित्रों का स्वागत है। डाक से खत भेजने के लिये पता है —

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद—121001

मालिक नहीं रहे, मैनेजमेन्टें हैं !!!

आज किसी फैक्ट्री के निर्माण व संचालन के लिये 100 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है तो उनका जुगाड़ 5 करोड़ रुपये के शेयरों और 95 करोड़ रुपये बैंक-बीमा-फन्ड से कर्ज ले कर किया जाता है। शेयरों में भी बड़ा हिस्सा बैंक-बीमा-इनवैस्टमेन्ट कम्पनियों का होता है। फैक्ट्री की जमीन, बिल्डिंगें, मशीनें कर्ज देने वालों के गिरवी होती हैं।

आज शेयर भी कर्ज ले कर खरीदे जाते हैं। सैटेलाइटों और कम्प्यूटरों से जुड़े बम्बई-टोकयो-न्यू यार्क-लन्दन-पेरिस-बर्लिन-मास्को- शंघाई-तेहरान के शेयर व मुद्रा बाजारों में थोक में सौदे होते हैं। कोई फैक्ट्री आज किस कम्पनी में है और कल किस कम्पनी में होगी, कोई कम्पनी आज किस ग्रुप में है और कल किस ग्रुप में होगी यह सट्टेबाजी तय करती है। फैक्ट्रियों के अब कोई मालिक नहीं हैं, फैक्ट्रियों को मैनेजमेन्टें संचालित करती हैं।

आज फैक्ट्रियों में मजदूर आठ-दस मिनट में अपनी ध्याड़ी के बराबर का उत्पादन कर देते हैं। आठ घन्टे की शिफ्ट में बाकी बचते 470 मिनट में मजदूर क्या करते हैं? बेगार। आठ घन्टे की शिफ्ट में कोई मजदूर दो घन्टे भी काम करता है तब भी वह अपनी तनखा से दुगने-तिगुने नहीं बल्कि 15 गुणा रुपयों के बराबर काम करता है।

तन और मन का यह हाल हो गया है कि स्वस्थ नजर आते मजदूर काम करते-करते अचानक मर जाते हैं।

लगातार बदतर होते जा रहे नाकाबिले बरदाश्त हालात को बनाये रखने के लिये विराट से विराटतर होते जा रहे मन्त्री-सन्तरी- अफसर-मानव संसाधन विकास विभागों के सम्मुख ईश्वर का विराट रूप बौना हो गया है।

आज हर फैक्ट्री के प्रोडक्शन का आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स रूप में एकत्र कर सरकारी तन्त्रों की उदर पूर्ति में खपता है। पन्द्रह परसैन्ट के करीब कर्जों पर ब्याज की अदायगी में जाता है। इतना ही शेयर होल्डरों के खाते में। पाँच-सात परसैन्ट मैनेजमेन्टों के ताम-झाम पर तथा रिश्वतें देने में। पाँच-सात परसैन्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर आदि लोग हेरा-फेरी कर लेते हैं। हेरा-फेरी वाले इन पाँच-सात परसैन्ट के लिये ही सरपंच-जनरल सैक्रेटरी - मेयर - सेनापति - मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री के पदों वाली मारा-मारी एम डी, जी एम के पदों के लिये होती है। मजदूर जो प्रोडक्शन करते हैं उसका एक परसैन्ट हिस्सा भी उनके पल्ले नहीं पड़ता।

कम्पनी बनी रहने पर ही हेरा-फेरियाँ चालू रह सकती हैं। इसलिए कम्पनी को क्लोजर-बंद होने से बचाने के लिये मैनेजमेन्टें जी-तोड़ कोशिश करती हैं। इस संदर्भ में मैनेजमेन्टें कानून-कायदों को तोड़ने के लिये इधर-उधर रिश्वतें भी खूब देती हैं। परन्तु सरकारों के टैक्स, मन्डी में डिमान्ड, मुद्राओं की दर, ब्याज के रेट मैनेजमेन्टों के बस से बाहर की चीजें हैं। अतः बड़ी संख्या में कम्पनियां बीमार होती हैं, फैक्ट्रियाँ बन्द होती हैं।

बीमार होने पर कम्पनी को जिंदा रखने के लिये बैंक-बीमा-फन्ड-ई एस आई - लेबर डिपार्टमेन्ट - बिजली बोर्ड-टैक्स वाले अफसरों को मोटी रिश्वतें दे कर मैनेजमेन्टों द्वारा कानूनों की धज्जियाँ उड़ाना आम बात है। इस सिलसिले में लीडरों की मिली-भगत से मैनेजमेन्टें मजदूरों का भी काफी पैसा फँसा देती हैं। बीमारी बढने पर हालात यह बनते हैं कि कम्पनी की सम्पत्ति से काफी ज्यादा की देनदारी कम्पनी के मत्थे मढ दी जाती है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्लोजर के मुहाने खड़ी कम्पनियों के मजदूरों द्वारा सरकारों-बैंकों-लीडरों पर आस रखने की कोई तुक नहीं है। और कोर्ट-कचहरी तो हैं ही थका कर मजदूरों को बिखेरने के जरिये। अतः अपने फँसे पैसे वसूलने के लिये, अपनी सर्विस - फन्ड - वेतन - बोनस-एल टी ए आदि की रकम हासिल करने के लिये मजदूरों द्वारा ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं जिनसे साहबों की नींद हराम हो। सामुहिक कदम मैनेजमेन्टों, लीडरों और सरकारों की नींद हराम करते हैं इसीलिए मजदूर इक्ट्ठे हो कर जब अपनी कोई बात कहने जाते हैं तब :

मैनेजमेन्टें कहती हैं कि भीड़ से बात नहीं हो सकती और अनुशासन भंग होता है इसलिए पाँच नुमाइन्दे चुन कर बात करने भेजो ;

लीडर कहते हैं कि मजदूर खुद ही बात करने लगेंगे तो लीडरों की जरूरत ही क्या रह जायेगी ;

सरकारें कहती हैं कि भीड़ से कानून व व्यवस्था भंग होती है इसलिए मजदूर अपने लीडर चुन कर साहबों-मंत्रियों के पास भेजें।

नीचे की दो घटनाओं को इस संदर्भ में देखें।

इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

सन्डे, 19 मई को सुबह 9 बजे मुजेसर थाने पर इकट्ठे हो कर एक लम्बी कार, दो मारुति वैन, दो मारुति कार, एक पुलिस जिप्सी, एक पुलिस वैन और दो मिनी ट्रकों के काफिले में 50-60 पुलिसवाले और 30-40 लफंगे इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड पहुँचे। ट्रक फैक्ट्री में और पुलिस व लफंगे गेट पर। बने हुये सवा करोड़ रुपयों के एयर कन्डीशनर लोड करने ही लगे थे कि फैक्ट्री में मौजूद चार-पाँच इलेक्ट्रोनिक्स वरकर वहाँ पहुँचे। हँगामा। पुलिस फैक्ट्री में दाखिल। धमकियाँ। इलेक्ट्रोनिक्स मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। 11 बजे लफंगे व पुलिसवाले जैसे आये थे वैसे ही लौट गये।

5 साल से प्रोविडेन्ट फन्ड और ई एस आई के पैसे नहीं जमा करवाये ; 1995 से डी ए नहीं दिया ; 1995 में रिटायर होने वालों व मर जाने वालों के सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे नहीं दिये ; क्लर्कों-टेक्निशियनों-सुपरवाइजरों को जून 95 से और अन्य मजदूरों को नवम्बर 95 से वेतन नहीं दिया ; 1994 का बोनस नहीं दिया,.....और 1 फरवरी 96 से इलेक्ट्रोनिक्स मैनेजमेन्ट फैक्ट्री नहीं आ रही। मजदूरों द्वारा रात-दिन फैक्ट्री में चौकसी और लीडरों द्वारा कोर्ट-कचहरी व अफसरों-मन्त्रियों के चक्कर। 26 फरवरी से फैक्ट्री पर बैंक के भी गार्ड। पूरी फरवरी सब इलेक्ट्रोनिक्स कर्मचारी रोज फैक्ट्री आते रहे। मार्च में संख्या में कुछ कमी आई। अप्रैल में यह और घटी। और 19 मई की घटना के समय चार-पाँच वरकर ही फैक्ट्री में थे।■

झालानी टूल्स

जनवरी 96 की तनखा मैनेजमेन्ट ने 2 मई को देनी आरम्भ की। एक चौथाई मजदूरों को भी वेतन नहीं दिया गया था कि 4 मई को लीडरों के एक गिरोह ने हड़ताल थोप दी। झालानी टूल्स के आम मजदूरों का फिकरा था, "तनखा तो लेने देते !" मैनेजमेन्ट ने "काम नहीं, वेतन नहीं" के नोटिस लगाये। डेढ साल पहले एक गिरोह ने अपने दबदबे के लिये 14 दिन की हड़ताल थोप कर प्रत्येक झालानी मजदूर को डेढ हजार रुपये की चपत लगाई थी और अब 31 मई तक ....

इन दस-पन्द्रह वर्षों में झालानी टूल्स में लीडरों के गिरोहों में आयाराम-गयाराम का इतना बोलबाला रहा है कि कौन कब किस गिरोह में था/है का हिसाब लगाने की कोशिश करें तो दिमाग चकरा जाये। दरअसल इन घनचक्करों में मजदूरों के करोड़ों रुपये डुबा दिये गये हैं और पन्द्रह-बीस करोड़ रुपये फँसा दिये गये हैं।

मन्डी की महिमा के चलते गेडोर हैन्ड टूल्स के जर्मनी स्थित तीन प्लान्ट बन्द हो गये और भारत स्थित छह प्लान्ट दलदल में धँसते ही जा रहे हैं। गेडोर के फरीदाबाद स्थित तीन प्लान्टों को आटोमेशन-छँटनी के जरिये जिंदा रखने के लिये ट्रकों में हथियारबन्द पुलिस ने चक्कर लगाये और एक प्लान्ट के अन्दर पुलिस चौकी बनाई तथा मैनेजमेन्ट और लीडरों ने मार-मार कर डेढ हजार मजदूरों से इस्तीफे लिखवाये। बात बनी नहीं – गेडोर हैन्ड टूल्स झालानी टूल्स बन गई। (**बाकी पेज चार पर**)

फैक्ट्री में क्लासें

अप्रैल के आरम्भ से 6 से 2 की शिफ्ट वालों के लिये 11 से डेढ तक और 2 से 10 वालों के लिये 3 से 5 बजे तक 24 सैक्टर स्थित **हिन्दुस्तान वायर्स** में मैनेजमेन्ट क्लासें लगाती है। पहले-पहल सुबह की शिफ्ट में पढाने दिल्ली से एक आता था और रोज के दो हजार रुपये लेता था। अब परसनल मैनेजर हफ्ते में सातों दिन पाठ पढाता है और जब प्लान्ट बन्द होता है तब जनरल मैनेजर भी अपने चेम्बर में बुला कर पढाने लगता है।

16 मई को हिन्दुस्तान वायर्स के एक मजदूर ने बातचीत में कहा, "बकवास करते हैं। जिस काम को हम जानते हैं उसी को उल्टा पढाते हैं। हम काम करते समय जो पाँच-दस मिनट के ब्रेक लेते हैं उसे वे खत्म करने का पाठ पढाते हैं। कहते हैं कि क्वालिटी के बारे में, वेस्ट के बारे में जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। पहले जो तार चलता था उसमें सिर्फ एक जगह डाई के पास धागा बाँधा जाता था। अब जब से पढाना शुरु किया है तबसे आठ जगह धागा बाँधना पड़ता है। किसी को प्यास लगी हो तो भी पहले धागा बाँधना पड़ता है। इन दो महीनों में ही काफी काम बढा दिया है। कम्पनी चाहती है कि 8 घन्टे काम में जुते रहें, खून-पसीना बहाते रहें, थोड़ा भी आराम नहीं करें।"

दिल्ली से पढाने आने वाला जब क्वालिटी-क्वालिटी और आई एस ओ- आई एस ओ कर रहा था तब मजदूरों ने उससे कहा, "कम्पनी हम से काम बढिया लेना चाहती है पर पैसे कम देती है तो हम टेन्शन में रहते हैं। घर में आटा नहीं है, किसी बच्चे के कपड़े नहीं हैं तो किसी के पास कापी-पेन्सिल नहीं है. . . .तनखा के दिन की कह कर टालते हैं। और तनखा हमें मिलती है 1300-1400। ऐसे में हम क्वालिटी कैसे सुधार कर दे सकते हैं।" तनखा के बारे में सुन कर वह मजदूरों के सामने मैनेजमेन्ट को गालियाँ देने लगा।

आई एस ओ मिलने से हमारे कितने पैसे बढाये जायेंगे का सवाल फिर वरकरों ने क्लास में परसनल मैनेजर के सामने रखा। साहब ने तब कहा कि आई एस ओ पैसा बढाने के बारे में नहीं होती, यह तो काम के बारे में होती है।

और खर्च में आई एस ओ लागू करते हुये हिन्दुस्तान वायर्स मैनेजमेन्ट क्लास में बैठने वाले वरकरों को दो मजदूरों के हिसाब से एक पेन्सिल दे कर कहती है कि आधी-आधी पेन्सिल ले लो।

मई के आरम्भ में कैन्टीन में खराब खाने के विरोध में हिन्दुस्तान वायर्स मजदूरों ने दो दिन कैन्टीन में खाना नहीं खाया।■

इस अंक की हम पाँच हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट पा रहे हैं। पाँच हजार मजदूर अगर हर महीने एक-एक रुपया दें तो दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

चाय रेखा

25 सैक्टर में सोहना रोड़ पर स्थित **मौर्या उद्योग** के एक क्वालिटी कन्ट्रोल इन्सपैक्टर ने कहा "मौर्या उद्योग में जहाँ तक चाय जाती है वहाँ तक स्टाफ है। जहाँ चाय रुक जाती है वहाँ से वरकर शुरु हो जाते हैं।"

लेकिन फ्लेक्सीबल का जमाना है इसलिये मौर्या मैनेजमेन्ट भी लचीली है। चाय की सीमा रेखा के अनुसार उसने क्वालिटी कन्ट्रोल इन्सपैक्टरों को वरकरों की कैटेगरी में अवश्य रखा है पर मौका पड़ने पर उन्हें स्टाफ भी करार देती है।

मौर्या मैनेजमेन्ट ने मार्च के ओवर टाइम के पैसे जब 18 मई तक नहीं दिये तब वरकर इकट्ठे हो कर जी एम के पास गये। साहब ने कहा कि पैसे 20 को दे दिये जायेंगे। नहीं दिये गये। वरकर फिर इकट्ठे हो कर पहुँचे तो साहब ने कहा कि 21 को दे दिये जायेंगे। 21 को भी नहीं दिये गये। मजदूरों ने सुपरवाइजरों और फोरमैन को टोकना शुरु कर दिया। मैनेजमेन्ट ने 24 मई को पैसे दिये। 24 को क्वालिटी कन्ट्रोल इन्सपैक्टर भी अपने ओवर टाइम के पैसे लेने पहुँचे तो मौर्या मैनेजमेन्ट ने कहा, "पैसे कम हैं और आप लोग स्टाफ में हो इसलिये आपको बाद में दिये जायेंगे।"■

सामुहिकता और मजदूर (पेज एक का शेष)

ऐसे में हर कोई **सोच-समझ कर राजी से जो कदम उठाने को तैयार होगा/होगी** वह छह इंच या उससे छोटा कदम ही हो सकता है।

मजदूर जब मिलजुल कर कदम उठाते हैं तब वे **कदम आमतौर पर छोटे-छोटे होते हैं।** इसलिये ऐसा करने के लिये किसी को गरम करने की जरूरत नहीं होती,

किसी में हवा भरने की जरूरत नहीं होती,
किसी से कोई बात छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं होती,
भाषण-कला नहीं चाहिये,
ड्रामेबाजी नहीं चाहिये,
लीडर नहीं चाहियें
और कानून-वानून से कोई हाथ नहीं बँधे होते।

विचार-विमर्श कर, राजी से मिलजुल कर मजदूर जो कदम उठाते हैं उन्हें सामुहिक कदम कहते हैं। शब्द नया लग सकता है पर मजदूर हर जगह रोज ही यह कदम उठाते हैं और फिर यह संघर्ष, आन्दोलन जैसा भारी-भरकम शब्द भी नहीं है। सामुहिक कदम मैनेजमेन्टों, लीडरों और सरकारों के गलों में फन्दे हैं।■

झालानी टूल्स (पेज तीन का शेष)

कम्पनी का क्रिकेट ग्राउन्ड नाम का प्लाट बेचा गया ; स्टाफ की हाउसिंग की जमीन बेची गई; प्रोविडेन्ट फन्ड में पाँच साल पैसे नहीं जमा कराये ; मन्दिर बनवाया ; मनहूस पेड़ कटवाये गये; अशुभ तीसरी मंजिल गिराई गई ; दक्षिण मुखी गेट और तुला राशि....

कम्पनी का दलदल में धँसना जारी रहा।

बैंक अफसरों को मोटी रिश्वतें दे कर और कर्ज लिये गयें ; लीडरों के लिये प्लाट-कोठी का प्रबन्ध कर मजदूरों के आठ घन्टे के काम को चार घन्टे का प्रोडक्शन करार दिया गया और कच्चे माल-बिजली-दुरुस्त मशीन के प्रबन्ध की जिम्मेदारी मजदूरों पर डाल कर तनखायें काटी गई.

कम्पनी का दलदल में धँसना जारी रहा।

पुराने लीडर नये लीडर बने। हर वरकर की तनखा में से दस रुपये काट कर वेतन के समय मैनेजमेन्ट ने बाइस-तेइस हजार रुपये लीडरों को देने शुरु किये। मजदूरों की हाउसिंग की 22 एकड़ जमीन बेच कर पैसे लूटे गये और कम्पनी में लगाये गये ; वेतन में दस परसैन्ट कटौती; चार महीनों की तनखा बकाया; फिर दो साल से पी एफ जमा नहीं कराया है....

नये-पुराने-नये लीडर नई सौगातें लिये हैं।

मजदूरों का 4 महीने का और स्टाफ का 7 महीनों का वेतन ; सात साल का प्रोविडेन्ट फन्ड; 5 साल के वर्दी-जूते ; दो साल का एल टी ए .... बकाया हैं। यह राशि छह-सात करोड़ रुपये है। और प्रत्येक झालानी मजदूर की सर्विस-ग्रेच्युटी का तीस-चालीस-पचास हजार रुपया भी दलदल की भेंट चढ़ाया जा रहा है। वरकरों की सर्विस-ग्रेच्युटी की रकम दस करोड़ रुपयों से ज्यादा बैठेगी।

कम्पनी की सम्पत्ति से काफी ज्यादा का कम्पनी पर कर्ज हो जाने की वजह से और कहीं से पैसे मिल नहीं रहे इसलिये मजदूरों के पैसे फँसाये जा रहे हैं। मैनेजमेन्ट और लीडर तो मजदूरों के पैसों को और फँसायेंगे – अपने पैसों के बारे में विचार करना झालानी टूल्स मजदूरों का काम है।■

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–548 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।